[श्री अशोक गहलोत]

रिकार्डर, कैसेट, विदेशी कपड़ा, घी इत्यादि लाया जाता है एवं इसके बदले में भारत से पशु धन, पान के पत्ते, नगीने, रम, शराब की बोतलें, बीड़ियों पैकेट व फिल्मी किताबे बड़ी मात्रा में तस्करों द्वारा ले जाई जाती है। पाकिस्तान जाने वाला यह सामान वहां बेहद लोकप्रिय होने से तस्करों को भारी मुनाफा भी होता है। लेकिन अभी चौथे वर्ष लगातार अकाल पड़ने से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पशु पालकों तथा उनके पशुओं की हालत दयनीय हो गई है। वे जब अपनी गायों का जंगलों में चरने हेतु छोड़ते हैं तो तस्कर लोग गायों इत्यादि को मौका पा कर हक्ला कर पाकिस्तान की तरफ ले जाते हैं एवं वहां पाकिस्तान की सीमा पर तस्करों के हाथों सौंप कर उन से विदेशी सोना व अन्य सामग्री प्राप्त कर लेते हैं।

मैं रक्षा मंत्री व गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अविलम्ब सीमावर्ती चौकियों को निर्देश दें जिससे सख्ती से पेश आ कर सीमा पर हो रही पशुओं व अन्य कीमती सामग्री की तस्करी को रोका जा सके।

(v) SETTING UP OF A TUBE-WELLS CORPORATION IN RAJASTHAN TO AUGMENT WATER RESOURCES.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): I wish to bring the following matter of urgent public importance to the attention of the House under Rule 377:—

Even after 34 years of independence of our country, Rajasthan still remains one of the States which cannot provide even drinking water to all its villages and villagers have to work 4 Kms. to tetch drinking water. Time and again it has been stressed that a Tubewell Corporation may be formed at the State level which can look after the interests of farmers and take the responsibility of digging a tubewells, because, at higher level the water is not fit for drinking; and even for irrigation purpose it is not useful. So, this Corporation would select places where water is fit for drinking as well as for irrigation purposes and could be utilised.

This Corporation would help in removing this deficiency and black-spot on the history of Rajasthan. On the one hand we are trying to send water in the space to a man who is arbitting in the sky, and, on the other hand, we cannot afford to give a glass of water to a citizen who is ploughing in the fields, working as labourer on the development schemes for the future of India. But the whole nation cannot give an assurance that he will have a glass of water whenever he needs it: I urge upon the Central Government to take up the matter with the State Government and help in all possible forms to remove this black spot from the history of Rajasthan and let soon there be a day when every citizen of the State at least could have food and water which is the minimum requirement for survival

(vi) WORKING OF HINDUSTHAN SAMACHAR NEWS AGENCY.

आचार्य भगवान देव (अजमेर): मैं सदन का ध्यान राष्ट्र भाषा हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में काम करने वाली समाचार एजेंसी, हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों में व्यापत असन्तोष की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके कारण संस्था के बन्द होने की सम्भावना निकट दिखलाई पड़ती है।

हिन्दुस्तान समाचार के प्रबन्धकों ने अभी पालेकर एवार्ड लागू नहीं किया है। सिर्फ उसे कागज पर लागू किया है और

उसके कारण कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन हर मास बाकी रख लिया जाता है। इस मद में अब तक कर्मचारियों के करीब 3 लाख रुपये बाकी पड़ चुके हैं। दूसरी ओर पालेकर एवार्ड लागू करने के नाम पर प्रबन्धकों ने बहुत से कर्मचारियों को गलत तरीके से पदोन्नत कर उन्हें वरिष्ठ सहयोगियों के सर पर बिठा दिया है।

इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि अक्तूबर, 1981 से जमा नहीं की गई है। प्रबन्धकों ने भविष्य निधि में अपना हिस्सा अप्रैल, 1980 से जमा नहीं किया है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एल० आई०) की राशि भी लम्बे अर्से से जमा नहीं हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों के परिवार चिकित्सा सेवा पाने से वंचित हो रहे हैं।

प्रबन्धकों ने 1979–80 का बोनस भुगतान करने के बजाय कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जमा रख लिया है। इसी प्रकार 1980–81 के बोनस का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। सब से चिन्ता का विषय यह है कि पत्रकार कर्मचारियों को जनवरी, 1982 से और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को फरवरी 1982 से वेतन अभी तक नहीं मिला है। 3–4 महीने के बाद वेतन देने की प्रक्रिया गत दो वर्षों से चल रही है।

वित्तीय संकट का बहाना बना कर वेतनादि भुगतान बन्द कर दिया है जिसके कारण कर्मचारियों ने मजबूर हो कर 16 अप्रैल, से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का निश्चय किया है। ,सरकार ने संस्था को सहायता के मद में काफी रुपये दिये। फिर भी प्रबन्धक संस्था को स्वावलम्बी बनाने में विफल रहे। प्रबन्धक समिति के भाषाई संवाद समितियों का एकीकरण कर उसे स्वाशासी निगम में रूपान्तरित किया जाय।

मैं श्रम मंत्री से निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों का बकाया वेतन और बोनस शीघ्र भुगतान कराने हेतु कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करें एवं भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा राशि की वसूली के लिए सख्त कार्यवाही करें।

4.35 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83.. *contd.*

Ministries of Agriculture and Rural Development—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We taken up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Mr. Ram Verma, you may continue your speech. You will conclude your speech by about 2.45. Then the hon. Minister will intervene. You can take about 10 minutes.

श्री जय राम वर्मा (फैजाबाद) : श्रीमन्, मैं कल कह रहा था कि हमारे जिले के पूर्वी हिस्से अकबरपुर में एक कोआपरेटिव सैक्टर में गन्ना मिल की स्थापना का लाइसेंस कांग्रेस सरकार ने दिया था जिसे जनता सरकार ने कैंसिल कर दिया था। हमारा जिला उत्तर प्रदेश के 7 सबसे पिछड़े हुये जिलों में एक है और पूर्वी हिस्से का गन्ना रत्ना शुगर मिल को अलाट होता है जो सिक मिल है, और इस साल काफी परेशानी हो रही है, किसानों का गन्ना बिल्कुल नहीं पैरा जा सका क्योंकि वह मिल अक्सर बन्द रहती है। इस उत्पादकता वर्ष में कांग्रेस सरकार इन बातों का ख्याल रख कर के उस गन्ना मिल का लाइसेंस